भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2566

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

19 फाल्गुन, 1942 (शक)

डाटा सेंटर अवसंरचना

2566. श्री भोला सिंह :
डॉ. जयंत कुमार राय :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेजी से आपस में जुड़ती हुई दुनिया में डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा के लिए भारत में डाटा केंद्र अवसंरचना ढांचे का विकास देश के लिए आवश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का डाटा सेंटर इन्सेंटीवाइजेशन (डीसीआई) योजना और डाटा सेंटर इकोनोमिक जोन (डीसीईजेड) योजना शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने हाल ही में डाटा सेंटर नीति, 2020 के लिए मसौदा जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत को वैश्विक डाटा सेंटर हब में बदलने और देश को दुनिया के लिए एक वैश्विक डाटा सेंटर बनाने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत में डेटा सेंटर बाजार में वृद्धि दूरसंचार, डिजिटल उपभोक्ताओं, उभरते व्यवसायों, डिजिटल सरकार और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सृजित आंकड़ों की मात्रा के साथ है। इस प्रकार, देश में डेटा सेंटर के अवसंरचना की आवश्यकता पहले से ही प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक के तहत डेटा स्थानीयकरण प्रावधानों के साथ सिंक में निवेश के लिए एक संभावित अवसर को खोलती है। देश के भीतर डेटा होस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, डेटा केंद्र क्षेत्र को सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे भारत में डेटा सेंटर के अवसंरचना को विकसित करने के लिए सुविधा प्रदान कर सकें।

(ग) और (घ) : अभी तक, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) : जी हाँ इस मंत्रालय की वेबसाइट पर 5 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 जारी की गई थी। प्राप्त इनपुट्स के आधार पर, नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी को ग्लोबल डाटा सेंटर हब बनने के लिए भारत में अंतिम रूप देने योग्य बनाया जा रहा है।

****